Further, development of airports of international standards with private paricipation at Mumbai. Bangalore. Hyderabad and Goa are under examination. At Amritsar, the existing airport is proposed to be upgraded to international standards, at an estimated cost of Rs. 120 crores, during the 9th plan period.

At least five cities are being identified for devleopment/construction of world-class international airports with 100% foreign investment. A high-level Task Force under the Chairmanship of Dy. Chairman, Planning Commission is looking into this proposal to identify the locations for the new world-class international airports.

Setting up Cargo hubs at International Airports

*228. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 156 given in the Rajya Sabha on 1st December, 1998, and state:

(a) how Government propose to meet the expendure to be incurred on developing Delhi as a 'Major Cargo Hub';

(b) whether Government intends to extend this scheme of cargo hubs to all other international airports in the country; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ANANTH KUMAR): (a) Delhi Airport is being developed as a major cargo hub and one of the features will be to have the proposed joint venture project in which the AAI will have minimum equity participation. Meantime works are in hand for expansion of the existing cargo terminal at Delhi at a cost of Rs. 42 crores and which are expected to be completed by April, 2000.

(b) and (c) Yes, Sir. Depending on the experience gained at Delhi Airport, such cargo hubs at other international airports in the country would be taken up.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले समयोपरि भत्ते की दरें

*229. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कई वर्षों से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है;

(ख) क्या पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के साथ ही कर्मचारियों के वेतनमानों तथा उनको मिलने वाले अन्य प्रकार के भत्तों में काफी वृद्धि की गई है; और क्या समयोपरि भत्ते की दरों में वृद्धि करना वाजिब है; और

(ग) यदि हां, तो आपरेटिव स्टाफ सहित केन्द्रीय सरकार के समयोपरि भत्ते की संशोधित दरें लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय समयोपरि भत्ते की वर्तमान दरें चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतनमानों में संशोधन के पश्चात् मार्च 1991 में संशोधित (दिसम्बर 1990 से लागू) की गई थीं। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में समयोपरि भत्ते को खत्म करने की सिफारिश के साथ-साथ यह भी सिफारिश की थी कि स्टाफ कार ड्राइवर, कार्यरत कर्मचारियों (ऑपरेशनल स्टाफ) और प्रौद्योगिकी कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ते का भुगतान उपरोक्त विषय पर जारी वर्तमान नियमों और अनुदेशों से अधिशासित करते हुए जारी रखा जाए। यह निर्णय लिया गया है कि समयोपरि भत्ते की पात्रता को और अधिक सीमित करने हेतु मामलों की समीक्षा के साथ-साथ सरकारी काम के हित के अनुरूप ही प्रतिबंधित करते हुए समयोपरि भत्ते के भुगतान की यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। तद्नुसार अगले आदेशों तक वर्तमान नियमों के अनुसार संबंधित कर्मचारी को पूर्व संशोधित वेतनमान/वेतन परिधि में वर्तमान आदेशों में निहित प्रयोग मूलक वेतन के आधार पर प्राप्त समयोपरि भत्ते का भुगतान जारी रखा गया है।

गुजरात में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए ऋण

*230. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं ने गुजरात में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए